

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 160
No. 193]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941	[N.C.T.D. No. 160

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 22/2018-राज्य कर (दर)

**सं.फा. 03(7)/वित्त(राज.-1)/2018-19/डीएस-VI/368.**—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किंतु 27 दिसंबर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का, अधित्यजन करती है:

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व, उन प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd September, 2019

**No. 22/2018-State Tax (Rate)**

**No. F.3 (7)/Fin (Rev-I)/2018-19/DS-VI/368.**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in FORM GST TRAN-1 was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in FORM GST TRAN-1 on or before the 10th day of May, 2018 and the return in FORM GSTR-3B for each of such months on or before the 31st day of May, 2018.

2. This notification shall come into force with effect from the 14th day of May, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**सं.12/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(3)/वित्त(राज.-1)/2018-19/डीएस-VI/369.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/364, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 8/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 और जिसको सं0फा0 03(101)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/165, तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) अधिसूचना सं.10/2018- राज्य कर (दर), तारीख 28 मार्च, 2018, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "30 जून 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए० के० सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**टिप्पणः—**मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं०फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/364, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 8/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सं०फा० 03(101)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/165, तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.10/2018- राज्य कर (दर), द्वारा किया गया था।

#### NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

#### No. 12/2018– State Tax (Rate)

**No. F. 3 (3 )/Fin (Rev-I)/2018-19/ DS-VI/369.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.8/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no.F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/364 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No.10/2018- State Tax (Rate), dated the 28th March, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(101)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/165 dated 28th March, 2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30th day of June, 2018”, the figures, letters and words “30th day of September, 2018” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 29th day of June, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secretary VI (Finance)

**Note:—**The principal notification No.8/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/364 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No.10/2018-State Tax (Rate), dated the 28th March, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(101)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/165 dated 28th March, 2018.

**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**संख्या 13/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(8)/वित्त (राज.-1)/2018-19/डीएस-VI/370.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV, सं0फा0 03 (15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/381 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

**क.** मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -

(3)	(4)	(5)
<p>“(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैम्प साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो</p> <p><u>स्पष्टीकरण 1:</u> इस प्रविष्टि में किसी कैटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो।</p> <p><u>स्पष्टीकरण 2:</u> इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं।</p> <p><u>स्पष्टीकरण 3:</u> “घोषित टैरिफ में” ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के</p>	2.5	<p>बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)</p>

लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा।		
(क) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसेंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)

**ख.** मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

**ग.** मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया :-

(3)	(4)	(5)
"(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका की मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो।	9	-";

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
<p>"(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन</p> <p><b>स्पष्टीकरण -</b></p> <p>(1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन;</p> <p>(2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरदेशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है;</p> <p>(3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-</p>	6	-

<p><b>क)</b> ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;</p> <p><b>ख)</b> प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो ।</p>		
(vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों ।	9	-”;

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“22	शीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं)	<p>(i) केवल ई-बुक की आपूर्ति स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलेक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है ।</p> <p>(ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं ।</p>	2.5	-
			9	-”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**टिप्पण :**—मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग VI, में सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI /381, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सं0फा0 03(85)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस- VI /97, तारीख 23 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.1/2018- राज्य कर (दर) तारीख 23 फरवरी 2018, द्वारा किया गया था ।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd September, 2019

**No. 13/2018- State Tax (Rate)**

**No. F. 3(8)/Fin (Rev-I)/2018-19/ DS-VI/370.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide noF.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 381, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 7, in column (3)-

a. for item (i), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
<p>“(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent;</p> <p><u>Explanation 1:</u> This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such supply is not event based or occasional.</p> <p><u>Explanation 2:</u> This item excludes the supplies covered under the item. 7 (v).</p> <p><u>Explanation 3:</u> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.</p>	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
<p>(ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.</p>	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]”;

(b) in items (ii), (vi) and (viii),-

- a. for the words “declared tariff” wherever they occur, the words “value of supply” shall be substituted;
- b. the Explanation shall be omitted;

(c) for item (v), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
<p>“(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.</p>	9	”;

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
<p>“(vi) Multimodal transportation of goods.</p> <p><i>Explanation.-</i></p> <p>(a) “multimodal transportation” means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;</p> <p>(b) “mode of transport” means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;</p> <p>(c) “multimodal transporter” means a person who,-</p> <p>(A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight, and</p> <p>(B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.</p>	6	-
(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	”;

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“22	<p><b>Heading 9984</b></p> <p>(Telecommunications, broadcasting and information supply services.)</p>	<p>(i) Supply consisting only of e-book</p> <p><i>Explanation.-</i></p> <p>For the purposes of this notification, “e-books” means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device.</p>	2.5	-
		(ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above.	9	”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27<sup>th</sup> day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note:—**The principal notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide noF.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No.1/2018-State Tax (Rate), dated the 23rd Feb, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(85)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/97 dated 23rd Feb, 2018.



**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**सं०. 14/2018-राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(5)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/371.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं०. 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV सं०फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/380 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

- (क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, “केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या” का लोप किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, “केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9घ	अध्याय 99	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10क	शीर्षक 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”;

- (ड) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

- (झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षम 9971 या शीर्षक 9991	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, (का 46 1948) 1948 द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31ख	शीर्षक 9971 or शीर्षक 9991	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।)	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

- (ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	शीर्षक 9971	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

		ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।		
--	--	--	--	--

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: -

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"47क</b>	शीर्षक <b>9983</b> या शीर्षक <b>9991</b>	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं*;

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"55क</b>	शीर्षक <b>9986</b>	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं*;

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"65ख</b>	शीर्षक <b>9991</b> या कोई अन्य शीर्षक	एक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।  स्पष्टीकरण:- "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमों या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो।	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी

			एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।*
--	--	--	--

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"77A"</b>	शीर्षक <b>9995</b>	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- (i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोत्तन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु.) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु।	कुछ नहीं	कुछ नहीं;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा।”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**नोट:—** मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग VI, में सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सं.फा. 03(84)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/75, तारीख 13 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 2/2018- राज्य कर (दर) तारीख 13 फरवरी 2018, द्वारा किया गया था।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd September, 2019

**No. 14/2018- State Tax (Rate)**

**No. F. 3 (5) /Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/371.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

- (a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words “Central Government, State Government, Union territory, local authority or” shall be omitted;
- (b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words “Central Government, State Government, Union territory, local authority or” shall be omitted;
- (c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9D	Chapter 99	Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty five thousand rupees per month per member provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance.	Nil	Nil”;

- (d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10A	Heading 9954	Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use.	Nil	Nil”;

- (e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words “declared tariff”, the words “value of supply” shall be substituted;
- (f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted;
- (g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted;
- (h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24A	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of warehousing of minor forest produce.	Nil	Nil”;

- (i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Coal Mines Provident Fund Organization to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).	Nil	Nil
31B	Heading 9971 or Heading 9991	Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee.	Nil	Nil";

- (j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading 9971	Services supplied by Central Government, State Government, Union territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions.	Nil	Nil";

- (k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after the figures "36" the word and figures "or 40" shall be inserted;

- (l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading 9983 or Heading 9991	Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators.	Nil	Nil";

- (m) after serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55A	Heading 9986	Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses).	Nil	Nil";

- (n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65B	Heading 9991 or any other Heading	Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders.  <i>Explanation.-</i> "mining lease holder" means a person who has been granted	Nil	Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of

		mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.		assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.”;
--	--	---	--	---

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“77A	Heading 9995	Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,- (i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or (ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment, to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year.	Nil	Nil”;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27<sup>th</sup> day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note:—**The principal notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification No. 02/2018-State Tax (Rate), dated the 13<sup>th</sup> Feb, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(84)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/75 dated 13<sup>th</sup> Feb, 2018.

**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**संख्या 15/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(6)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/372.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक/नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं।	बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स	ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो।";

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

‘(छ) “अचल संपत्ति को किराए पर देने” से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसेंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**टिप्पणः**—मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VII/379, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सं.फा. 03(91)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/98, तारीख 23 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2018- राज्य कर (दर) तारीख 23 फरवरी 2018, द्वारा किया गया था।



**NOTIFICATION**Delhi, the 2<sup>nd</sup> September, 2019**No. 15/2018- State Tax (Rate)**

**No. F.3 (6)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/372.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379 dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	Services supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank/ non-banking financial company (NBFCs)	Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm	A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable territory.”;

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(g) “renting of immovable property” means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.’.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27<sup>th</sup> day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note:** —The principal notification No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 03/2018-State Tax (Rate), dated the 23rd Feb, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(91)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/98 dated 23rd Feb, 2018.

**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**संख्या 16/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(7)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/373.**— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 14/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV

सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/378 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

- (i) प्रस्तावना में, “राज्य सरकार” शब्दों के पश्चात “या संघ राज्य क्षेत्र” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) “पंचायत को” शब्दों के पश्चात “या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को” अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट:—प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/378 दिनांक 30 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

#### No. 16/2018-State Tax (Rate)

**No. F.3(7)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/373.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.14/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/378 dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) after the words “State Government” the words “or Union territory” shall be inserted;
- (ii) after the word “Constitution” the words “or to a Municipality under Article 243W of the Constitution” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27<sup>th</sup> day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, notification No.14/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/378 dated 30th June, 2017.

**अधिसूचना**

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**सं. 17/2018- राज्य कर (दर)**

**सं.फा. 03(8)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/374.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381 दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ‘कारोबार’ की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

**नोट:**—प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 के रूप में दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सं.फा. 03(85)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस- VI/ 97, तारीख 23 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.1/2018- राज्य कर (दर) तारीख 23 फरवरी 2018, द्वारा किया गया है।

**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd September, 2019

**No. 17/2018- State Tax (Rate)**

**No. F.3 (8)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/374.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated 30th June, 2017, hereby inserts following explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation. - For the purposes of this item, the term, ‘business’ shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of July, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note:—**The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 IV, vide no. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 01/2018-State Tax (Rate), dated the 23th Feb, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(85)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/97 dated 23th Feb, 2018.